Industrial policy for the North-East

2380. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Ministry of Finance turned down various proposals of fiscal benefit envisaged in the new Industrial Policy for rapid industrialisation in the North-East;

(b) if so, the details thereof and reaction of Government thereto, item-wise; and

(c) the clause-wise factual position of the policy?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT) (a) No, Sir.

(b) Does not arise in view of (a) above.

(c) The item-wise detail of the North Eastern Industrial Policy is as follows:

1. Entire expenditure on Growth Centres, up to Rs. 15 crores would be met through Central assistance.

2. Funding pattern for Integrated Infrastructure Development Centres (IIDCs) changed to 4:1 between Government of India and SIDBI.

3. Transport subsidy scheme extended upto 31.3.2007 and amount to be disbursed through North East Development Finance Corporation.

4. Growth Centres & IIDCs become tax-free zones for income tax and excise for 10 years. 15% subsidy on Plant & Machinery subject to a ceiling of Rs. 30 lakhs would be given to units located therein.

5. An interest subsidy of 3% on the working capital loans would be provided for a period of ten years after the commencement of production.

6. Comprehensive Insurance Scheme for new industrial units.

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता

2381. **श्रीमती मालती शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों से निधि उपलब्ध होने में काफी कठिनाई हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान चमोली, पौड़ी और टिहरी जिलों में इस योजना के माध्यम से लाभान्वित हुए बेरोजगार युवाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) उनका जिला-वार ब्यौरा क्या हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिर्पोटों के अनुसार समूचे राज्य में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के कार्यान्वयन में आ रही सामान्य कठिनाइयों के अतिरिक्त, पहाड़ी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बहुत कम बैंक शाखाएं होने तथा दूर-दराज के क्षेत्रों से ऋणों की वसूली के कारण कतिपय अतिरिक्त कठिनाइयां महसूस की जा रही हैं।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षो, अर्थात्, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान, उत्तर प्रदेश के चमोली, पौड़ी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल जिलों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लाभ उठाने वाले बेरोजगार युवकों का जिलेवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।